

सतना

16 जुलाई 2024
मंगलवार

दैनिक

मीडिया ऑडिटर

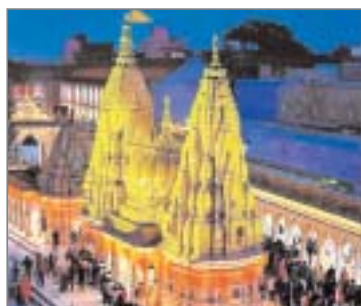
सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

जिम्बाब्वे दौरें...
@ पेज 7

वाराणसी- विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए काशीवासियों के अलग प्रवेश द्वार, आईडी कार्ड जरूरी

- काशीवासियों के लिए अलग द्वार से प्रवेश करने की सुविधा दी गई है
- सुबह चार से पांच बजे के बीच शिवलिंग का स्पर्श दर्शन
- शाम को चार से पांच बजे तक बाबा का झांकी दर्शन कर पाएंगे

वाराणसी (एजेंसी)। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए काशीवासियों के लिए अलग प्रवेश द्वार खोलने की चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब मंदिर प्रशासन की ओर से इसका सफल ट्रायल कर लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में रोजाना प्रवेश की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से काशीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी



सामने आई है। दरअसल, काशीवासियों विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए अलग द्वार की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन ने इसको लेकर सफल ट्रायल कर लिया है। कुछ दिनों में ही यह व्यवस्था रेगुलर कर दी जाएगी। 22 जुलाई से सवान की शुरुआत हो रही है, इसके कारण वाराणसी में कांवाडियों की भारी संख्या दिखेगी। ऐसे में मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए अलग द्वार मिलने से यहां के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत



हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है।

पूणिद्या-हटिया कोशी एक्सप्रेस से गन फॉरेट पर अधिकारी का अपहरण

पटना (एजेंसी)। बेगूसराय जिला के तेघरा थाना क्षेत्र के अम्बा निवासी रामानंद पाठक के पुत्र दीपक कुमार पाठक का सोमवार सुबह 9.15 बजे पूणिद्या-हटिया कोशी एक्सप्रेस ट्रेन से अपहरण कर लिया गया। दीपक, जो नव चर्याग्राम ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं, हाथीदह से ट्रेन में सवार हुए थे और गया जा रहे थे। उन्हें बाद में बख्तियारपुर में सकुशल बरामद किया गया।

संक्षिप्त समाचार

नीट: सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगी

- एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

अगली सुनवाई 18 जुलाई को

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाईकोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल, नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थीं।

राजीव कुमार फिर बने बंगाल के पुलिस के महानिदेशक, लोकसभा चुनाव के दौरान ईसी ने दिया था हटाने आदेश

कोलकाता (एजेंसी)। राजीव कुमार को फिर से बंगाल पुलिस के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया था।

कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सेवा पड़ी सरकार को महंगी

- 300 करोड़ घाटे के बाद अब 20 प्रतिशत किराया बढ़ाने की तैयारी

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में सरकार आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस सरकार आई और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही राज्य की बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी गई। हालांकि इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ रहा है और सरकार बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। कर्नाटक सड़क परिवहन के अध्यक्ष एस आर श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में सरकारी बसों के किराए में वृद्धि होनी चाहिए। श्रीनिवास ने कहा कि केएसआरटीसी ने राज्य सरकार को 15 से 20 प्रतिशत किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।



में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी गई। हालांकि इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ रहा है और सरकार बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। कर्नाटक सड़क परिवहन के अध्यक्ष एस आर श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में सरकारी बसों के किराए में वृद्धि होनी चाहिए। श्रीनिवास ने कहा कि केएसआरटीसी ने राज्य सरकार को 15 से 20 प्रतिशत किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

उड़व ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात

- मातोश्री पहुंचे शंकराचार्य बोले- सीएम बनने पर दूर होगा द्रष्ट



मुंबई (एजेंसी)। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उड़व ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मातोश्री का दौरा करने के बाद शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म में विश्वासघात बड़ा पाप है। उड़व ठाकरे के साथ यही हुआ है। वह विश्वासघात के भूकभोगी हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य के दोबारा सीएम बनेंगे तभी सब ठीक होगा।

बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और असम में बारिश का तांडव

- असम में बाढ़ का कहर, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 93
- दिल्ली में झमाझम कोकण में रेलवे ट्रेक पर गिरा मलबा, 7 ट्रेन प्रभावित
- उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 10 लाख लोग हुए प्रभावित
- महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू

उ.प्र.-बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब, मुंबई में गाड़ियां बही, 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली/लखनऊ/पटना/मुंबई (एजेंसी) देशभर में जारी भारी बारिश का दौर थमता नहीं दिख रहा है। कई राज्यों में अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे कई लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों में कुछ क्षेत्रों में अत्यंत भारी तो, कुछ में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम में लगातार बारिश हो रही है। इससे इन राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 से ज्यादा पर्यटक सौंदर्यों पर पानी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि, कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा रत्नागिरी और चंद्रपुर में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे इन जिलों में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। खेड में दीवानखावटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रेक पर मलबे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर चार से पांच घंटे लेट हैं।



शाह ने की मुयमत्रियों से बात

इधर, बाढ़ के हालातों को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा-

तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजाराभत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। एआईएमपीएलबी की वकिंग कमेटी ने एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की।

इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि यह फैसला 'शरिया' (इस्लामी कानून) के खिलाफ है। लिहाजा एआईएमपीएलबी सभी संभावित उपायों का पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को पलटने को कह सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144) के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है।



तलाक घिनौनी चीज, शादी बनाए रखने की हर कोशिश होनी चाहिए- पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा कि बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि पैगंबर ने कहा था कि जिन चीजों को करने की इजाजत दी गई है, उसमें से तलाक सबसे घृणित चीज है। लिहाजा शादी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए सभी वैध उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही इसके बारे में कुरान में जो दिशानिर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। हालांकि, अगर वैवाहिक जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है, तो तलाक को मानवीय समाधान के तौर पर देखा जा सकता है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी करना यह फैसला- प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि बोर्ड को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन महिलाओं के लिए और ज्यादा समस्याएं पैदा करेगा जो अपने दर्दनाक रिश्तों से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी हैं। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बैठक के बाद बताया कि एआईएमपीएलबी ने अपने अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी को इजाजत दी है कि वे सभी कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक उपाय करके देखें जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा जा सके।

देश का पहला हाइड्रोजन कूज पहुंचा काशी

वाराणसी (एजेंसी)। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला कूज वाराणसी पहुंच गया है। कोलकाता के कोक्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए शिप देर शाम नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में रामनगर मल्टी-मॉडल टर्मिनल राहपुर में खड़ा किया गया। यहीं पर शिप की सजावट और लाइटिंग का काम किया जाएगा।

यह डबल डेकर कैटमरान कूज जून के अंतिम सप्ताह में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रोकना पड़ा। इसके चलते जलयान को आधा सफर पूरा करने में ज्यादा समय लगा।

50 सीटर शिप वाराणसी से चुनाव के बीच चलेगा- इस जलयान को पर्यटन विभाग वाराणसी से मिर्जापुर के चुनाव के बीच करीब 15 किमी की दूरी में चलाएगा।

शहीद के पेरेंट्स-पत्नी को इश्योरेंस फंड के 50-50 लाख मिले

आर्मी बोली- पेंशन पत्नी को मिलेगी, क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। सियाचिन में सेना के टेंट में आग लगने से 19 जुलाई 2023 को शहीद हुए देवरिया के कैप्टन अंशुमान के परिवार को आर्मी ग्रुप इश्योरेंस फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए। यह रकम अंशुमान के पेरेंट्स और उनकी पत्नी में आधी-आधी बांटी गई। शहीद के माता-पिता ने कहा था- बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सम्मान लेकर चली गईं। हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए।

इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा है कि आर्मी की ओर से पेरेंट्स को 50 लाख और पत्नी को 50 लाख दिए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इसमें से 15 लाख माता-पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए।



म.प्र. धार भोजशाला

एएसआई ने म.प्र. हाईकोर्ट में सौंपी 2000 पेज की रिपोर्ट

दावा- 94 टूटी प्रतिमाएं मिलना मंदिर होने का सबूत

भोपाल/ इंदौर (एजेंसी)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने धार में स्थित भोजशाला की साइटिफिक स्टडी कर 2,000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। करीब तीन महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने-अपने दावे किए हैं। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दावा किया जा रहा है कि यहां 94 से ज्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद की गई हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी दो हजार पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। अब 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाईकोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा? इधर हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो साबित करता है कि यहां मंदिर था।

हिंदू पक्ष ने कहा-

हमारा पक्ष मजबूत, सुप्रीम कोर्ट जाएं

हिंदू फूट ऑफ जस्टिस के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एएसआई रिपोर्ट में हमारे केस को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने हमने कहा था कि यह परिसर एक हिंदू मंदिर का है। इसका इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो रहा है। 2003 में एएसआई ने जो आदेश पारित किया था, वह पूरी तरह गलत है। देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने एएसआई को साइटिफिक स्टडी के निर्देश दिए थे। दो हजार पेज की रिपोर्ट में हमारा पक्ष मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर स्टे दे रखा है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वकील हरि शंकर जैन कहते हैं कि आज बहुत खुशी का मौका है। हिंदू जनता सदियों से धार में पूजा करने के लिए तरस रही थी, जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे और पहली याचिका जो हिंदुओं की तरफ से मने दाखिल की थी, उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ये बात रिपोर्ट में साबित हो गई, प्रमाणित हो गई है, कोई इसे काट नहीं सकता कि वहां पहले हिंदू मंदिर था।

बच्चों की पढ़ाई और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास



तीन महिलाओं के खिलाफ केस

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। भोपाल के आनंद नगर में बच्चों की अच्छी पढ़ाई और रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। यह तीनों महिलाओं पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर उनको हिरासत में ले लिया है।

पुलिस का कहना है कि रविवार को वे शिवनगर में लोगों ने आकर बताया कि वह घरों में जाकर उन्हें लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता धनवीर सिंह ठाकुर उर्फ उमेश ठाकुर को भी मतांतरण का प्रलोभन दिया, जिसके बाद उन्होंने पिपलानी थाने में शिकायत की, शिकायत के आधार पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण अधिनियम के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार धनवीर सिंह ठाकुर कोकता इलाके में रहते हैं। वह

बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और आनंद नगर में पुलिस चौकी के पास ही उनकी दुकान है। रविवार की शाम को वे अपने दोस्तों से मिलने शिव नगर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं पर्चे बांट रही हैं साथ ही लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रही हैं।

उन्होंने देखा कि वहां पर महिलाएं अपने धर्म प्रचार से संबंधित बात कर रही थीं। इसी दौरान एक महिला उनके पास आई तथा उसने धनवीर से धर्म के बारे में पूछा। धनवीर ने अपना धर्म बताया तो महिला ने एक पर्चा थमाते हुए कह दिया कि अगर आप हमारा धर्म अपना लें तो हम आपको 20 लाख रुपये देंगे। साथ ही आपके बच्चों की पढ़ाई की खर्चा भी उठाया जाएगा।

महिला की यह बात सुनते ही धनवीर को समझ आया कि महिलाएं लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार कर रही हैं। उन्होंने पिपलानी पुलिस को मामले की शिकायत कर दी। रात करीब साढ़े आठ बजे एफआइआर रजिस्ट्री स्टॉफ को लेकर वहां पर पहुंच गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब भी महिलाएं पर्चे बांट रही थीं।

मप्र पर्यटन बोर्ड सिनेमा में निवेश के लिए लाया योजना



मिलेगी 75 लाख रुपए तक की सब्सिडी

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। मध्यप्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मप्र पर्यटन बोर्ड द्वारा बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति निवेशकों को सिनेमा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिए फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020 अंतर्गत निवेशकों को 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है।

सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए, मौजूदा सिनेमाघर के उन्नयन के लिए 75 लाख रुपए और मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में अभी तक कम निवेशकों ने ही इसका लाभ उठाया है।

प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश को फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथ

ही फिल्म से जुड़ी आधारभूत संरचनाएं विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। दो वर्षों में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 25 लाख पर 15 फीसदी राशि का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपए है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय एक करोड़ रुपए पर 15 फीसद अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपए है।

अनुदान के लिए करना होगा आवेदन: इच्छुक निवेशक और सिनेमा हॉल मालिक अनुदान के लिए आधिकारिक पोर्टल 222.द्वद्वद्वद्व-द्वद्व.द्वद्वद्वद्वद्व-द्वद्व.द्वद्व से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की सूची उल्लेखित है। आवेदन पत्र के साथ व्यापारिक योजना, वित्तीय विवरण और सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण के साथ आवश्यक दस्तावेज एमपी टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा।

नर्सिंग स्कैम, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। एनएसयूआई ने सोमवार को नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी उनके साथ थे।

कांग्रेस तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और वाटर कैनन भी छोड़ी। पुलिस की कार्रवाई से कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया।

कांग्रेस नेता भी रहे प्रदर्शन में



शामिल: इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व

मंत्री जयवर्धन सिंह समेत अन्य शामिल हुए। जीतू पटवारी ने कहा कि एनएसयूआईने छात्रों के हितों को लेकर प्रदर्शन किया। मगर पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए,

लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया।

कांग्रेस नेता भी रहे प्रदर्शन में शामिल: इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के

साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत अन्य शामिल हुए। जीतू पटवारी ने कहा

कि एनएसयूआईने छात्रों के हितों को लेकर प्रदर्शन किया। मगर पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए, लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया।

एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का नया फरमान, हर दिन पांच उपभोक्ता से बात करें सभी अधिकारी

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा फरमान जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारी रोज 5-5 बिजली उपभोक्ताओं से बात करें। विद्युत व्यवस्था और उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित फीडबैक लें। इस आदेश के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश में लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। रोज कहीं ना नहीं बिजली के तार टूटने और खराब होने की समस्या आती रहती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि अधिकारी बिजली उपभोक्ताओं के साथ लगातार बात करें। किसी भी हालत में संवादहीनता नहीं होना चाहिए। विद्युत वितरण केंद्र, जोन, संभाग स्तर पर डेली बिजली उपभोक्ताओं से बात किया जाए।



प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख उपभोक्ता: उन्होंने कहा है कि वह स्वयं भी बिजली उपभोक्ताओं से बात करेंगे। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रबंध संचालक और मुख्य अभियंता भी प्रतिदिन कुछ उपभोक्ताओं से चर्चा कर उपभोक्ता संतुष्टि पर फीडबैक लेंगे। तोमर ने कहा कि

प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। ये सभी तीन बिजली कंपनियों पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र की कंपनियों से जुड़े हैं। बिजली का आपूर्ति प्रभावित होने से सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं को होता है। इसलिए उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क बनाना जरूरी है।

बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने काम की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी वे झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं तो कभी वे खुद शौचालय साफ करने लगते हैं। पिछली सरकार में भी वे मंत्री थे। एक बार तो वे नाला की सफाई के लिए खुद नाले में उतर गए थे।

एमपी में आने वाला है 75,000 करोड़ रुपए का निवेश

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश की नई सरकार एक बार फिर से निवेशकों को प्रोत्साहित करने में जुटी है। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों के साथ वन टू वन बात की थी। बातचीत के दौरान एमपी में निवेश के कई बड़े प्रस्ताव आए हैं। मुंबई से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में इसकी जानकारी दी है। होटल इंडस्ट्री से लेकर रक्षा क्षेत्र तक में निवेशकों ने निवेश की बात कही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार रीजनल इनवेस्टर कॉन्क्लेव कर रही है। उज्जैन के बाद जबलपुर में कॉन्क्लेव है।

अनिल अंबानी ने सबसे बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया: मुंबई में सीएम मोहन यादव ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की है। इस दौरान रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के सीएम ने सिंगरौली और अन्य जिलों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। साथ ही गोंदरंज



कज्यूरमंडल इंडस्ट्रीज के एमडी के मालनपुर में 450 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। इसके

साथ ही ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के एमडी एचके अग्रवाल ने नागदा और मैहर में 4000 करोड़ रुपए निवेश की

बात कही है। जेएस डब्ल्यू लिमिटेड ने बैतूल, शहडोल और दमोह में 17,000 करोड़ रुपए निवेश का

प्रस्ताव दिया है। साथ ही योटा डेटा सर्विस ने इंदौर में 500 करोड़ और एल एंड टी ने इंदौर में 2000 करोड़ रुपए निवेश की बात कही है। इन निवेशों से मध्य प्रदेश में कुल एक लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अनिल अंबानी डिफेंस के क्षेत्र में भी यहां निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जबलपुर में निवेश करना चाहते हैं।

दूरिज्म के क्षेत्र में भी आया निवेश: इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दूरिज्म के क्षेत्र में भी कई निवेश आएंगे। देवास और बांधवागढ़ में महिंद्रा होलिडे 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ओबेरॉय हॉटल ग्रुप भी 400 करोड़ रुपए लगाएगी। साथ ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में साज हॉटल ग्रुप निवेश करेगी।

जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव: इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इसमें शामिल होने के लिए 1500 निवेशकों ने सहमति दी है। इस मौके

में अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी आएंगे। जबलपुर के अलावे के सितंबर में ग्वालियर और रीवा में अक्टूबर में इंडस्ट्री समिट का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम आईटी सेक्टर के निवेशकों को लुभाने के लिए कोयम्बटूर, बैंगलोर, दिल्ली और इंदौर में भी इंडस्ट्री समिट करेंगे। साथ ही रोड शो भी करेंगे।

भोपाल में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट: वहीं, पहली बार इंदौर के तर्ज पर भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसका आयोजन 7-8 फरवरी 2025 को होगा। इसका थीम द फ्यूचर रेडी स्टेट रखा गया है। इसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम हर क्षेत्र में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, जमीन लेकर निवेश नहीं करने वालों पर सीएम ने कहा कि उसमें हमारा क्या जाता है। अगर वह नहीं लगाएंगे तो जमीन वापस ले लेंगे। रीजनल क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं।

चौथी मंजिल की बालकनी में बैठी

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। कमला नगर इलाके में स्थित परिसर की चौथी मंजिल से गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। महिला अपनी बेटी के घर डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी, तभी फ्लेट की बालकनी से महिला अपनी नियंत्रण खो बैठी और गिर गई।

पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 73 वर्षीय भूपेंद्र कोर खजुरी में रहती हैं। उनका बेटा कनाडा में रहता है, जबकि बेटी की शादी हो चुकी है, और वह सहय्यदी परिसर में रहती हैं। कल सुबह महिला अपनी बेटी के घर पर आई थी, जहां से उन्हें डॉक्टर को दिखाना



वृद्धा की गिरने से मौत

था। इसी बीच चौथी मंजिल पर स्थित फ्लेट की बालकनी से वह नीचे गिर गई थी। हादसे में घायल महिला को उनकी बेटी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पहले महिला के परिजन पीएम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में पुलिस की समझाइश के बाद वह पीएम कराने को राजी हुए।

पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में मामला हादसा लग रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की

जांच में जुटी हुई है। **अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान:** बिलखिरिया पुलिस ने बताया कि बलराम गुर्जर पुत्र गोरालाल गुर्जर (50) ग्राम बावड़िया खुर्द में रहता था, और मेहनत मजदूरी करता था। कल दोपहर उसने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। अभी पुलिस ने पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सुराइट नोट भी पुलिस को नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस जांच करने की बात कह रही है।

एमपी पुलिस प्रदेश में अपराध को रोकने ला रही एआई, साबित होगा वरदान

मीडिया ऑडिटर, भोपाल (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश पुलिस राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करने वाली है। पिछले अपराध डेटा के निवारक डेटा विश्लेषण का उपयोग करने की योजना बना रही है। गृह विभाग ने राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को पिछले एक साल के अपराध डेटा को इकट्ठा करने के लिए लिखा था। ब्यूरो द्वारा मैप का इस्तेमाल करने और रंग चिह्नित करने और फिर उस डेटा को विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध एआई उपकरणों का उपयोग करने के लिए लिखा है।



राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास पूरा अपराध डेटा उपलब्ध है। सूत्रों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विश्लेषण किए जाने पर यह डेटा हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद

करेगा। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में अपराध के पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है। जिसके उपयोग के बाद में पहचाने गए हॉटस्पॉट में संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए काम किया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि डेटा का विश्लेषण करने के बाद, आउटपुट जिला अधिकारियों को भेजा जाएगा। जिससे वे अपने जिलों में पहचाने गए हॉटस्पॉट के पैटर्न आदि के अनुसार निवारक उपाय कर सकें। ये उपाय गश्त बढ़ाना, स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, पैटर्न के अनुसार वर्ष के विशिष्ट समय या अवधि में गश्त बढ़ाना हो सकते हैं।

विचार

पूँजीगत खर्चों में वृद्धि एवं मध्यवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान की जानी चाहिए

जुलाई 2024 माह में शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक बजट पेश किया जाने वाला है। हाल ही में लोक सभा के लिए चुनाव भी सम्पन्न हुए हैं एवं भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंप दी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। अब केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शीघ्र ही केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले लगातार दो वर्षों के बजट में पूँजीगत खर्चों को और इस सरकार का विशेष ध्यान रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूँजीगत खर्चों के लिए किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस राशि में 33 प्रतिशत की राशि की भारी भरकम वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूँजीगत खर्चों के लिए किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 11 प्रतिशत ही अधिक है। इस राशि को यदि 33 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इसे कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए की राशि के स्थान पर 12.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान पूँजीगत खर्चों के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए पूँजीगत खर्चों में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है और फिर भारत ने तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक विकास दर की रफ्तार को पकड़ा ही है। आर्थिक विकास की इस वृद्धि दर को बनाए रखने एवं इसे और अधिक आगे बढ़ाने के लिए पूँजीगत खर्चों में वृद्धि करना ही चाहिए। आर्थिक विकास दर में तेजी के चलते देश में रोजगार के नए अवसर भी अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत अधिक आवश्यकता भी है। भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान विकास की दर को तेज करने के चलते ही लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के ऊपर उठ पाए हैं एवं करोड़ों नागरिक मध्यवर्ग की श्रेणी में शामिल हुए हैं। अब भारत में गरीबी की दर 8.5 प्रतिशत रह गई है जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में 21.1 प्रतिशत थी। गरीबी की रेखा से बाहर आए इन नागरिकों एवं मध्यवर्गीय नागरिकों ने देश में उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, कर संग्रहण में भी इस वर्ष ने महती भूमिका अदा की है। आज प्रत्यक्ष कर संग्रहण लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर भी अब औसतन लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह से अधिक की राशि के संग्रहण के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि का लाभांश केंद्र सरकार को उपलब्ध कराया है तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ अर्जित कर केंद्र सरकार को भारी भरकम राशि का लाभांश उपलब्ध कराया है, जबकि कुछ वर्ष पूर्व तक केंद्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के चाटे की आपूर्ति हेतु इन बैंकों को बजट में से भारी भरकम राशि उपलब्ध करानी होती थी। कुल मिलाकर इस आमूल चूल परिवर्तन से केंद्र सरकार के बजटीय घाटे में भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है।

केंद्र सरकार का बजटीय घाटा कोविड महामारी के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक हो गया था जो अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 5.1 प्रतिशत तक नीचे आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार, अब यह सिद्ध हो रहा है कि केंद्र सरकार ने न केवल अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने में सफलता अर्जित की है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करने में सफलता पाई है। पूँजीगत खर्चों में वृद्धि के साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में मध्यवर्गीय नागरिकों को आय कर की राशि में छूट देने का प्रयास भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किया जाना चाहिए। क्योंकि, प्रत्यक्ष कर संग्रहण में हो रही भारी भरकम 25 प्रतिशत की वृद्धि इसी वर्ग के प्रयासों के चलते सम्भव हो पा रही है। वैसे, भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार भी नागरिकों/करदाताओं पर करों का बोझ केवल उतना ही होना चाहिए जितना एक मधुमक्खी किसी फूल से शहद लेती है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में अधिक राशि पहुंचने का सीधा सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को ही होता है। मध्यवर्गीय नागरिकों के हाथों में यदि खर्च करने के लिए अधिक राशि पहुंचती है तो वह विभिन्न उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देता है इससे इन उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होती है और इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर अर्थव्यवस्था में निर्मित होते हैं एवं कम्पनियों द्वारा विनिर्माण इकाइयों का विस्तार किया जाता है तथा निजी क्षेत्र में भी पूँजीगत निवेश बढ़ता है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के चक्र को बढ़ावा मिलता है जो अंततः देश के कर संग्रहण में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। मध्यवर्गीय परिवार के आय कर में कमी करने से बहुत सम्भव है कि भारत में औपचारिक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले।

धर्मोन्मूलन पर न्यायालय की चिन्ता और सरकार की उदासीनता

मनोज ज्वाला

महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'क्रिश्चियन मिशनरिज- देयर प्लेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के 'टॉक विथ मिशनरिज' अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है।



मनोज ज्वाला

खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अनुसूचित जातीय-जनजातीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्रिश्चियनिटी अथवा इस्लाम में तब्दील किए जाने के व्यापक रिलीजियस-मजहबी अभियान चिन्ता जताते हुए कहा है इसे यदि रोका नहीं गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी शीघ्र ही अल्पसंख्यक हो जाएगी या मुसलमान और तब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी; अतएव सरकार कठोर कानून बना कर इस अभियान पर तत्काल रोक लगावे। ऐसी ही चिन्ता पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय भी जता चुका है। हालांकि दोनों ही न्यायालयों ने इसे %ईसाईकरण% अथवा 'इस्लामीकरण' की संज्ञा देते हुए ऐसा कहा है, किन्तु मेरा मानना है कि यह धर्मांतरण कतई नहीं है, अपितु यह तो 'धर्मोन्मूलन' है; क्योंकि बहुसंख्यक समाज धर्मधारी है और क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, तो इस्लाम भी एक मजहब है। इन दोनों में से 'धर्म' कोई नहीं है, तो जाहिर है कि धर्मधारी लोगों को रिलीजन या मजहब में तब्दील कर देना उनके धर्म का उन्मूलन ही है 'अंतरण' तो कतई नहीं; यह धर्मांतरण तो तब कहलाता, जब एक धर्म से दूसरे धर्म में अन्तर्ण होता, अर्थात्, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी कोई धर्म होता। बहरहाल, धर्मोन्मूलन को धर्मांतरण ही मानते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को जो निर्देश दिया है सो त्वरित क्रियान्वयन के योग्य है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड में धर्मधारी प्रजा (बहुसंख्यक हिन्दू समाज) के ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण का छद्म अभियान चला रहे रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं को परोक्षतः कराया जवाब देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को धर्म से विमुख किया जाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्वोच्च न्यायालय का तो यह भी मानना है कि इस प्रकार के अभियान से भारत राष्ट्र की एकता-अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है; अतएव इसे रोका जाना अनिवार्य है। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता व मान्यता भारत के 'राष्ट्रीय युवा'- स्वामी विवेकानन्द और महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द के चिन्तन-उद्बोधन पर आधारित है।

मालूम हो कि स्वामी विवेकानन्द ने कह रखा है कि धर्मांतरण एक प्रकार से राष्ट्रान्तरण है। धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति जब 'रिलीजन' व 'मजहब' को अपना लेता है, तब वह प्रकारान्तर से भारत के विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि धर्म तो भारत की आत्मा है, जबकि 'रिलीजन' व 'मजहब' अन्धकार की अवधारणा हैं। इसी तरह से महर्षि अरविन्द का कथन है कि धर्म (सनातन) ही भारत की राष्ट्रीयता है और धर्मांतरण से भारतीय राष्ट्रीयता क क्षरण अवश्यभावी है। भारत के इतिहास और भूगोल में यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। भारत-विभाजन अर्थात् पाकिस्तान-युज्जन और खण्डित भारत के भीतर यत्र-तत्र रिलीजियस-मजहबी जनसंख्या के बढ़ते आकार से उत्पन्न विभाजनकारी पृथकतावादी आन्दोलन इसके प्रमाण हैं। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'क्रिश्चियन मिशनरिज- देयर प्लेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के 'टॉक विथ मिशनरिज' अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है। आगे वे कहते हैं- भारत में ईसाइयत अर्थात् युरोपीकरण का जो काम करती रही हैं, उन कामों के लिए स्वतंत्र भारत में उन्हें कोई भी स्थान एवं अवसर नहीं दिया जाएगा; क्योंकि वे समस्त भारतवर्ष को नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ऐसी किसी चीज का होना एक त्रासदी है। सन 1935 में चर्च-मिशनरियों का एक प्रतिनिधि से हुई भेंटवार्ता में महात्मा साफ कहा था- अगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकूँ तो मैं धर्मांतरण का यह सारा धंधा ही बन्द करा दूंगा। (सम्पूर्ण गांधी वांगमय- खण्ड 61) बावजूद इसके आज देश भर में ऐसी रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, जो शिक्षा-स्वास्थ्य-सेवा के विविध प्रकल्पों और सामाजिक न्याय व समता-स्वतंत्रता के विविध आकर्षक सज्जबागों एवं विकास-परियोजनाओं की ओट में देसी-विदेशी धन के सहारे छलपूर्वक धर्मांतरण का धंधा संचालित कर रही हैं। इन संस्थाओं की कारगुजारियों के कारण यहां कभी

'असहिष्णुता' का ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाता है, तो कभी 'अल्पसंख्यकों की सुरक्षा' का ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ बताया जाता है। ये संस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति की हैं। कुछ शैक्षणिक-अकादमिक हैं, जो शिक्षण-अध्ययन के नाम पर भारत के विभिन्न मुद्दों पर तरह-तरह का शोध-अनुसंधान करती रहती हैं; तो कुछ संस्थायें ऐसी हैं, जो इन कार्यों के लिए अनेकानेक संस्थायें खड़ी कर उन्हें साध्य व साधन मुहैया करती-कराती हुई विश्व-स्तर पर उनकी नेटवर्किंग भी करती हैं। %फ्रीडम हाउस% संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी ही संस्था है, जो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें भडकाने के लिए विभिन्न भारतीय-अभारतीय संस्थानों का वित्त-पोषण और नीति-निर्धारण करती है। किन्तु वास्तव में धर्मोन्मूलन (अर्थात् ईसाईकरण या इस्लामीकरण) और भारत-विभाजन ही इसका गुप्त एजेण्डा है, जिसके लिए यह संस्था भारत में कथित अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की इच्छा-दुष्क्री घटनाओं को भी बढ़ा-चढ़ा कर दुनिया भर में प्रचारित करती है। इसी तरह से 'दलित फ्रीडम नेटवर्क' (डीएफएन) नामक एक अमेरिकी संस्था का नियमित पाक्षिक प्रकाशन भी है- 'दलित वायस' जो भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर एक पृथक 'दलितस्तान' राज्य की भी वकालत करता रहता है। इन दोनों संस्थाओं को अमेरिकी सरकार का ऐसा वरदहस्त प्राप्त है कि वे अमेरिका-स्थित विभिन्न सरकारी आयोगों के समक्ष भारत से रिलीजियस-मजहबी कार्यकर्ताओं को ले जा- ले जाकर भारत-सरकार के विरुद्ध गवाहियां दिलाता है।

ये संस्थायें भारत के बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध फर्जी अल्पसंख्यक-उत्पीड़न और उसके निवारणार्थ भारत-विभाजन की वकालत-विषयक शैक्षिक शोध-परियोजनाओं के लिए शिक्षार्थियों व शिक्षाविदों को फेलोशिप व छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसने कांचा इलाइया नामक उस तथाकथित दक्षिण भारतीय शोधार्थी को उसकी पुस्तक- 'ह्वै आई एम नॉट ए हिन्दू' के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों-ईसाइयों को स्वयं हिन्दुओं के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध के लिए भडकाया गया है।

पीआईएफआरएएस (पॉलिसी इंस्टिट्यूट फॉर रिलीजन एण्ड स्टेट) अर्थात् 'पिफ्रास' अमेरिका की एक और ऐसी संस्था है, जिसका चेहरा तो समाज और राज्य के मानवतावादी लोकतान्त्रिक आधार के अनुकूल नीति-निर्धारण को प्रोत्साहित करने वाला है, किन्तु इसकी खोपड़ी में भारत की वैविध्यतापूर्ण एकता को खण्डित करने और हिन्दुओं के धर्मांतरण ('धर्मोन्मूलन') की योजनायें घुमती रहती हैं। इन धर्मांतरणकारी मिशनरी संस्थाओं का एक वैश्विक गठबन्धन भी है, जिसका नाम- एफआईएकेओएनए (द फेडरेशन ऑफ इण्डियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गनाइजेशन ऑफ नार्थ अमेरिका) अर्थात् 'फिजाकोना' है। ये दोनों संगठन एक ओर 'इण्टरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम; नामक अमेरिकी कानून के सहारे विश्व-मंच पर भारत को 'मुस्लिम-ईसाई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़क देश' के रूप में घेरने की साजिशें रचते रहते हैं, तो दूसरी ओर भारत के भीतर नस्लीय भेद एवं सामाजिक फूट पैदा करने के लिए विभिन्न तरह के हथकण्डे अपनाते रहते हैं।

ऐसे में भारत की सम्पृभुता व अखण्डता की सुरक्षा के लिए धर्मांतरण (धर्मोन्मूलन) पर रोक लगाने के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इससे भी उच्च सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को निर्देशित किये जाने के बावजूद सरकार की उदासीनता घोर चिन्ताजनक है। धर्मोन्मूलन (धर्मांतरण) का सदैव ही विरोध करते रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जब अल्पसंख्यक-कल्याण के नाम पर बहुसंख्यक समाज के यीसाईकरण व इस्लामीकरण को बढ़ावा देने वाली पूर्व की कांग्रेसी सरकार द्वारा कायम किए गए अल्पसंख्यक आयोग एवं मुस्लिम वक्फ बोर्ड नामक संस्थाओं और उनकी विभिन्न योजनाओं यथा- 'मदरसाई शिक्षा', 'वजीफा' व व्याज-मुक्त ऋण आदि पर प्रति वर्ष भारी-भरकम बजट का प्रावधान करती रही है, तब इस राष्ट्रीय त्रासदी से भारत राष्ट्र को आखिर कौन उबारोगे? न्यायालय जब बहुसंख्यक समाज की घटती आबादी पर चिन्ता जताते हुए उसके ईसाईकरण व इस्लामीकरण को रोकने का निर्देश दे रहा है, तब केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह इसके उपाय के तौर पर इन धर्मोन्मूलनकारी (धर्मांतरणकारी) योजनाओं को बन्द करते हुए 'समान नागरिक संहिता' शीघ्र कायम करे और 'मजहबी आबादी नियंत्रण' का सख्त कानून भी कायम करे।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

नियंत्रण से बाहर होती मुद्रा स्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं एवं इन देशों का सामाजिक तानाबाना भी छिन्नभिन्न हो गया है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवाद हावी रहता है अतः स्थानीय समाज में विभिन्न परिवारों के बीच आपसी रिश्ते केवल आर्थिक कारणों के चलते ही टिक पाते हैं अन्यथा शायद विभिन्न परिवार एक दूसरे से रिश्तों को आगे बढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। कई विकसित देशों में तो पति-पत्नी के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। अमेरिका में तो यहां तक कहा जाता है कि 60 प्रतिशत बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है एवं केवल माता को ही अपने बच्चे का लालन-पालन करना होता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है एवं यह बच्चे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में हिंसा की दर बढ़ रही है तथा वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों के नागरिक अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं एवं उन्हें उम्मीद है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का हल भारतीय सनातन संस्कृति में से ही निकलेगा। अतः इन देशों के नागरिक अब भारतीय सनातन संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। भारत में वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों



ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंडकाल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों का

अपना रहे थे, ने भी पूँजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है। भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर

भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय घाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक तानाबाना छिन्नभिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। माननीय वित्तमंत्री महोदय को भी देश में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णतः असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रा स्फीति की दर वॉछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांतों को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात् आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के पांचवें खिलाड़ी के तौर पर तुषार देशपांडे ने किया डेब्यू

नई दिल्ली। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच हारने में खेला जा रहा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले और दूसरे मैच के बाद चौथे मैच में भारत ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दौरे पर भारत के पांचवें खिलाड़ी ने डेब्यू किया है। चौथे मैच में तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे को जगह दी गई है। वह आवेश खान की जगह टीम में खेलने उतरे हैं। तुषार देशपांडे ने डेब्यू कैप मिलने पर कहा कि, यहां आकर बहुत खुश हूँ, ये मेरे बचपन के दिनों की याद दिलाता है, जब मैंने



अपने देश के बारे में खेलने का सपना देखा था। नीली जर्सी पहनकर यहां आना बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है।

गुकेश और प्रज्ञानानंद 45वें शतरंज ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम में

चेन्नई। भारत के स्टार खिलाड़ी डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद हंगरी के बुडापेस्ट में सितंबर में होने वाले आगामी शतरंज ओलंपियाड में भाग लेंगे। नवंबर में विश्व शतरंज चैम्पियनशिप में चीन के मौजूदा विश्व चैम्पियन डिंग लिरेन को चुनौती देने वाले गुकेश के लिए यह टूर्नामेंट 'ड्रेस रिहर्सल' की तरह होगा। गुकेश (18 वर्ष) ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। वह अप्रैल में टोरंटो में कैडिडेड्स टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने पीटीआई को

पुष्टि करते हुए बताया कि टीम में अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती और पी हरिकृष्णा भी शामिल हैं। महिला टीम में डी हरिका, वैशाली रमेशबाबू, दिव्या देशमुख, वंशिका अग्रवाल और तानिया सचदेव मौजूद हैं। ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्मो अज्ञात कारणों से टीम से बाहर हैं जिन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता था। भारत ने पहली बार 2022 में ओलंपियाड के पिछले चरण की मेजबानी की थी जिसमें मेजबान देश ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीता था। यह ओलंपियाड का 45वां चरण होगा। हंगरी पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी मेजबानी करेगा।

यूरो कप फाइनल में स्पेन को जीतते देखना चाहते हैं बाईचुंग भूटिया



नयी दिल्ली। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ यूरो कप फाइनल में स्पेन को जीतते हुए देखना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि लेमिन यमल और निको विलियम्स शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर के प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। भूटिया ने कहा, "स्पेन का पलड़ा निश्चित रूप से फाइनल

में भारी होगा क्योंकि जिस तरह से वे खेल रहे हैं, उसे देखकर उनकी टीम पूरी तरह से संतुलित दिख रही है। वे तकनीकी रूप से अच्छा खेल दिखा रहे हैं। उन्होंने छह में से छह मैच जीते हैं। निश्चित रूप से स्पेन की टीम फॉर्म में है।" भारत के इस 47 वर्षीय महान स्टारड्रकर ने कहा, "यमल और विलियम्स फिर शानदार प्रदर्शन करेंगे।

वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार अपने होम टाउन पहुंचे हार्दिक पांड्या, मरीन ड्राइव जैसा दिखा माहौल

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टीम ने 29 जून को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भारत में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ देखने के लिए लाखों फैंस मुंबई के मरीन ड्राइव पहुंचे थे। टीम इंडिया ने 17 सालों के बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। भारत की जीत के बाद खिलाड़ियों को हर तरफ सम्मान किया जा रहा है। इसी बीच टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत की जीत के बाद अपने होम टाउन वडोदरा पहुंचे हैं। जहां उनके स्वागत में हजारों फैंस अपने घरों के बाहर आ गए। हार्दिक इस दौरान काफी खुश नजर आए।

अपने घर पहुंचे हार्दिक पांड्या: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जब से भारत पहुंचे हैं, उन्हें अपने होम टाउन जाने का समय नहीं मिल सका था। जिसके कारण वह देरी से अपने घर पहुंचे हैं। इसके बाद भी फैंस ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं की है। हार्दिक इस दौरान बस पर खड़े नजर आ रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस वहां मौजूद हैं। हार्दिक के वहां पहुंचते ही मुंबई के मरीन ड्राइव जैसा माहौल देखने को मिल रहा था। हार्दिक पांड्या ने भारत को वर्ल्ड कप जीताने में एक अहम रोल निभाया था। हार्दिक जब बस पर मौजूद थे तो वह अपने इंस्टाग्राम से लाइव भी आए थे। जहां फैंस हार्दिक-हार्दिक के नारे लगाते नजर आ रहे हैं।



कूछ महीने पहले हुए थे ट्रोल: हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ महीनों पहले आईपीएल के दौरान फैंस द्वारा भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। जब उन्हें रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंप दी गई थी। हार्दिक पांड्या की

कप्तानी में मुंबई की टीम प्लेऑफ तक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी। हार्दिक को हर वेन्यू पर फैंस ने ट्रोल किया था। अब यही ट्रोलर्स उनके फैन बन चुके हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी ओवर फेंका था। जहां उन्होंने डेविड

मिलर को आउट किया और आखिरी ओवर में 16 रन बचाए। इसके अलावा हार्दिक ने इस मुकाबले में क्लासेन को भी आउट किया था। रोहित शर्मा ने भी यह माना था कि हार्दिक के आखिरी ओवर के कारण टीम इंडिया यह मैच अपने नाम कर सकी थी।

भारतीय खिलाड़ी ने मांगी माफी अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखी बात



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों ने हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हिस्सा लिया। जहां उन्होंने पाकिस्तान की टीम को आखिरी ओवर में हराया और खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की थी। जोकि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने अपने साथी युवराज सिंह, सुरेश रैना और गुरकीरत मान के साथ एक

ऐसा वीडियो पोस्ट किया। जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। वीडियो के कारण मांगनी पड़ी माफी: टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके हरभजन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। जहां उन्होंने युवराज सिंह, सुरेश रैना और गुरकीरत मान के साथ मिलकर वीडियो बनाया था। इस वीडियो में चारों खिलाड़ी दिव्यांग की तरह एक्ट करते नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि 15 दिनों तक क्रिकेट खेलने के बाद उनका हालत ऐसी हो गई है। फैंस को इनका ये वीडियो पसंद नहीं आया और इसके लिए उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। अब इस

वीडियो के लिए हरभजन सिंह ने माफी मांगी है। हरभजन ने लिखी ये बात: हरभजन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि मैं बस अपने उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ जो यहां इंग्लैंड में चैंपियनशिप जीतने के बाद सोशल मीडिया पर तौबा तौबा के हमारे हालिया वीडियो के बारे में शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम हर व्यक्ति और समुदाय का सम्मान करते हैं और यह वीडियो सिर्फ 15 दिनों तक लगातार क्रिकेट खेलने के बाद हमारे शरीर के हालत के बारे में था।

जोकोविच विम्बलडन जीतकर बनाएंगे ये महारिकॉर्ड



नई दिल्ली। विम्बलडन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेला जाएगा। इस मुकाबले में सर्बिया के स्टार नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज आपस में भिड़ेंगे। लंदन में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक ने 25वीं सीड इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को सीधे सेटों में 6-4, 7-6 (2), 6-4 से हराया। कार्लोस अल्कारेज ने पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया था। मेदवेदेव मौजूदा विम्बलडन चैंपियन हैं। अल्कारेज ने पिछले साल नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब जीता था। अब जोकोविच का लक्ष्य सेंटर कोर्ट पर मिली हार का बदला चुकता करने पर होगा। जैसे कार्लोस अल्कारेज को हराना जोकोविच के लिए आसान नहीं रहने वाला है। अल्कारेज इससे पहले तीन बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे थे और जीत भी हासिल की थी। 21 वर्षीय अल्कारेज तीनों तरह के कोर्ट घास, क्ले और हार्ड पर ग्रैंडस्लैम ट्रॉफी जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

सिकंदर रजा ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास ऐसा करने वाले जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी बने

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है। जहां इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। दरअसल, वे जिम्बाब्वे की टीम के लिए टी20आई क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक और बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की है।

वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन और 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। सिकंदर रजा ने भारत के खिलाफ चौथे टी20आई मैच में ये उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा सिकंदर रजा ने भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा निजी स्कोर भी बनाया है, अभी तक वे भारत के खिलाफ 34 रन ही बना पाए थे। ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने जैसे ही भारत के खिलाफ हारारे में जारी चौथे टी20आई मैच में 13वें ओवर का आखिरी गेंद पर 17वां रन बनाया, वैसे ही वे जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर सीन विलियम्स हैं। उन्होंने 1691 रन जिम्बाब्वे के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए हैं। तीसरे नंबर पर हैमिल्टन मासकादजा हैं,



जिन्होंने 1662 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने भारत के खिलाफ 46 रनों की पारी केली। ये भारत के खिलाफ उनका सर्वाधिक स्कोर था। वहीं सिकंदर रजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के पांचवें ऑलराउंडर बन गए हैं। ऐसा करने वाले भी वे जिम्बाब्वे के पहले ही ऑलराउंडर हैं। उनके अलावा बांग्लादेश

के शाकिब अल हसन (2551 रन और 149 विकेट), अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (2165 रन और 96 विकेट), मलेशिया के विरनदीप सिंह (2320 रन और 66 विकेट) और पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज (2514 रन और 61 विकेट) ने 2000 प्लस रन और 50 प्लस विकेट निकाले हैं। रजा ने 2000 से ज्यादा रन और 65 विकेट टी20 आई में निकाले हैं।

आईसीसी बोर्ड टी20 विश्व कप के अमेरिकी चरण के खर्चों पर चर्चा कर सकता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी20 विश्व कप के अमेरिका चरण में बजट से अधिक खर्च होने का अनुमान है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड कोलंबो में 19 जुलाई को होने वाली वार्षिक बैठक के दौरान इस नुकसान पर चर्चा कर सकता है। टी20 विश्व कप की ऑडिटिंग (आय और व्यय का लेखा जोखा) पूरी नहीं हुई है, इसलिए नुकसान का आंकड़ा बताना मुश्किल है क्योंकि दर्शकों के टिकट से प्राप्त राशि की पूरी तरह से गणना की जानी बाकी है।

बोर्ड के प्रमुख सदस्यों का हालांकि मानना है कि टूर्नामेंट के अमेरिका चरण में हुआ नुकसान लाखों डॉलर में हो सकता है। यह पता चला है कि टूर्नामेंट निदेशक क्रिस टेल्ली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन घटनाक्रम से अवगत सूत्रों के अनुसार इंग्लैंड के 49 वर्षीय खेल प्रशासक ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इस्तीफा देने



का मन बना लिया था। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "कई सदस्य टेल्ली के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि टी20 विश्व कप के अमेरिका चरण का इससे कोई लेना-देना है।" उन्होंने कहा, "कम से कम तीन आईसीसी वैश्विक टूर्नामेंट और सभी सहयोगी देशों को टी20 अंतरराष्ट्रीय का दर्जा मिलने के कारण, प्रबंधन का काम निरंतर चल रहा है।

ऐसा माना जाता है कि टेल्ली ने कुछ समय पहले ही अपना पद छोड़ने का फैसला किया था।" जिन लोगों ने इस आयोजन के संचालन के लिए करीब से काम किया है, उनका मानना है कि आईसीसी वास्तव में टिकटों की बिक्री के माध्यम से अच्छी कमाई करेगी। जिस बात ने आईसीसी के प्रभावशाली सदस्यों को नाराज किया है, वह इस प्रमुख आयोजन के लिए न्यूयॉर्क शहर को एक मेजबान के तौर पर चुनना है। नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की पिच और

आउटफील्ड की काफी आलोचना हुई थी और इस स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने कहा, "यह आयोजन अमेरिका में होना था और न्यूयॉर्क के अलावा अन्य शहर भी थे जहां मैचों का आयोजन किया जा सकता था। इस पर विचार क्यों नहीं किया गया?" उन्होंने सवाल उठाया, "पिच के परीक्षण के लिए कोई अभ्यास मैच क्यों नहीं खेला गया। यह पिच निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के क्रिकेट के लिए अनुपयुक्त था।

सीएम हेल्पलाईन की कोई शिकायत नहीं रहे नाट अटेण्ड

डी श्रेणी में रही तहसील तो कटेगा तहसीलदार का वेतन, समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों से कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की कोई भी शिकायत बिना अटेण्ड उच्च स्तर पर नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की ग्रेडिंग के बाद जो भी विभाग डी श्रेणी में पाये जायेंगे। उस विभाग के अधिकारी की एक सप्ताह की सैलरी काटी जायेगी। बिरसिंहपुर तहसील में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर कलेक्टर ने 20 जुलाई की मोहलत दी है। ग्रेडिंग के बाद तहसील के डी श्रेणी में रहने पर संबंधित तहसीलदार की एक सप्ताह की वेतन काट दी जायेगी। कलेक्टर ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कहा कि पिछले सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम हुआ है। ग्रेडिंग के दौरान टाप टेन जिलों में बने रहने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, आयुक्त नरिण निगम शेर सिंह मीणा, एसडीएम एपी द्विवेदी, सुधीर बेक, जीतेन्द्र वर्मा, राहुल सिलाडिया सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।



कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कहा कि पिछले हफ्ते बेहतर काम होने से शिकायतें 17 हजार से घटकर 14 हजार पर आ गई हैं। सभी विभागों को और भी अधिक मेहनत करना आवश्यक है ताकि ग्रेडिंग के दौरान भी जिला अग्रणी पंक्ति में बना रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। रामपुर बधेलान तहसील में काफी सुधार हुआ है। लेकिन बिरसिंहपुर तहसील में अपेक्षित प्रगति नहीं आ

पाई है। सभी एसडीएम अपनी तहसील की सीएम हेल्पलाइन की मानीटरिंग करें। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी शिकायत अगली स्टेज तक नाट अटेण्ड नहीं जानी चाहिए। नाट अटेण्ड शिकायतों का पूरा वेटेज 10 प्रतिशत मिलना ही चाहिए। सतना जिला जून माह की शिकायतों के साथ अभी 6वें स्थान पर है। कुल 70 प्रतिशत वेटेज के साथ जिला बी श्रेणी में है। ग्रेडिंग के अनुसार स्वास्थ्य, श्रम, खनिज, जल संसाधन और राजस्व विभाग

डी श्रेणी में हैं। सभी विभाग चार दिनों में सीएम हेल्पलाइन पर फेकस कर डी श्रेणी से बाहर आये। सीएम हेल्पलाइन में प्रगति नहीं आने और 40 से अधिक शिकायतें लंबित पाये जाने पर कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारी नागोद, बिरसिंहपुर, उचेहरा, कोठी और सहायक श्रमायुक्त को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन, खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, प्रधानमंत्री आवास



योजना शहरी और ग्रामीण, राजस्व के बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में जवाब दाखिल करने और अवमानना के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की। कोर्ट के अवमानना के प्रकरणों में उचित कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित विभागों, आरटीओ, कार्यपालन यंत्री बाणसागर, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, नजूल, डीपीसी और जिला

शिक्षा अधिकारी एसडीएम रघुराजनगर शहरी और रामपुर बधेलान को कलेक्टर ने नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जवाब और की गई कार्यवाही भी पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश विभागों को दिये हैं। राजस्व अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर और अन्य निर्मित परिसरों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये।

शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 17 जुलाई

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। जिले की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए पंजीयन कार्य 11 जुलाई से शुरू होगा। आईटीआई में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र 'पेनबैण्ड' के माध्यम से वेब साईट पर जाकर रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिले में संचालित शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए एनसीवीटी/एससीवीटी के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 11 जुलाई 2024 से 17 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से विभाग के पोर्टल एकेकएनएचएचएचएच पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन-2024 पर जाकर 11 जुलाई 2024 से 17 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चयन सूची 24 जुलाई 2024 को जारी की जाएगी तथा चयन सूची अनुसार आवेदक 26 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2024 तक संबंधित संस्था में दस्तावेज सत्यापन करा कर प्रवेश ले सकते हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदक रजिस्ट्रेशन हेतु किसी भी नजदीकी ऑनलाइन सहायता केन्द्र अथवा स्वयं अपने स्तर पर कंप्यूटर या मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। शासकीय आईटीआई में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। समस्त इच्छुक आवेदक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग अवश्य करें। रजिस्ट्रेशन से संबंधित किसी भी सहायता के लिए आवेदक हेल्पडेस्क नंबर 9171257462, 8982018733, 9111749057 पर फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुपयोगी सामग्री से निर्मित कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु आवेदन 25 जुलाई तक

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। मैहर मां शारदा की पावन नगरी एवं संगीत संग्रहालय पत्र विभूषण बाबा अलाउद्दीन खां साहब की साधना स्थली मैहर में शास्त्रीय संगीत के उभरते हुये नवोदित कलाकारों को मंच देने का कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से मैहर म्यूजिक अटाला आर्ट सिटी के तत्वाधान में 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ किया गया है। मैहर म्यूजिक अटाला आर्ट सिटी के तत्वाधान में आयोजित होने वाले मासिक संगीत कार्यक्रम 1 अगस्त 2024 को संगीत महाविद्यालय कक्ष में पुराने अनुपयोगी सामग्री से निर्मित कलात्मक वस्तुओं की (अटाला आर्ट) प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जिसमें जिले के नागरिकण भाग ले सकते हैं। प्रदर्शनी हेतु केवल पुराने व अनुपयोगी सामग्री से निर्मित कलात्मक सामग्री को शामिल किया जायेगा। इस हेतु कलाकार अपने आवेदन बायोडेटा के साथ 25 जुलाई तक संगीत महाविद्यालय मैहर में प्रभारी अनिल कुमार जायसवाल, सहायक व्याख्याता (मोबा. 7987274350) के पास जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय समिति के द्वारा चयन किया जाकर आवेदकों को प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

स्वयं सेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 एवं 19 को

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान आपदा जोखिम क्षेत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विभिन्न हितधारकों की भूमिका को देखते हुए दो नवीन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। दोनों परियोजनाओं के प्रभावी रियान्वयन के लिए 18 एवं 19 जुलाई को जिला पंचायत सतना के सभाकक्ष में प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपम वर्मा ने उप संचालक सामाजिक न्याय, जिला कार्यर म महिला बाल विकास, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनके विभाग से मान्यता प्राप्त 25-25 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उपस्थित कराने के निर्देश दिये हैं। कार्यशाला प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रारंभ होगी। जिला कमाण्डेंट होमगार्ड को भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहने को कहा गया है।

डॉ. सुदाम खाड़े ने आयुक्त जनसंपर्क का पदभार ग्रहण किया

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। डॉ. सुदाम खाड़े ने आज जनसंपर्क संचालनालय में आयुक्त जनसंपर्क का पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान जनसंपर्क आयुक्त सदीप यादव ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जनसंपर्क संचालनालय में डॉ. खाड़े के पदभार ग्रहण करने पर संचालक रोशन कुमार सिंह, अपर संचालक



जीएस वाधवा, संजय कुमार जैन, मनोज खरे सहित सभी अधिकारी, कर्मचारियों ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 31 अगस्त तक चलेगा राजस्व महाअभियान

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दिए राजस्व महाअभियान के संबंध में निर्देश



मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। प्रदेश के सभी जिलों में 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को राजस्व महाअभियान की तैयारियों के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राजस्व महाअभियान में नक्शा सुधार और नक्शा तरमीम के सभी प्रकरण निराकृत करें। अभियान के दौरान सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को 15 अगस्त तक भू अधिकार फॉर्म का वितरण कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शेष बचे सभी किसानों की ई केवाईसी तथा आधार सीडिंग कराएं। अभियान के दौरान जमीन के खसरे में आधार सीडिंग की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान कमिश्नर कम से कम एक तहसील का निरीक्षण करें। कलेक्टर, अपर कलेक्टर और एसडीएम भी

तहसीलों का निरीक्षण करें। पटवारियों का निर्धारित मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें। इसका उल्लंघन करने वाले पटवारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की निष्पत्ति सुनिश्चित करके इनका निराकरण कराएं। खसरा सुधार के प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत करें। अभियान के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोंवश को गोंशालाओं में सुरक्षित कराएं। सड़कों पर पशुओं का विवरण न हो इसे सुनिश्चित करें। वर्षाकाल में कई बार संचारी रोगों का प्रकोप होता है। वर्षा जलित रोगों से बचाव के उचित प्रबंध करें। सभी कलेक्टर आगामी त्यौहारों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। धार्मिक स्थलों में उचित साफसफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था करें। आगामी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये प्रयास तेज पीएम जन-मन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल अंचलों में जारी हैं कई विकासमूलक कार्य

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 15 नवम्बर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारम्भ किया गया। पीएम जनमन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरीया विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की 11 लाख 85 हजार 374 आबादी को विभिन्न प्रकार की सहायता व रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण देकर इन्हें विकास की नई राह से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 11 चिन्हित अधोसंरचना विकासमूलक गतिविधियों एवं 7 हितग्राहीमूलक योजनाओं के घर पहुंच लाभ प्रदाय पर केन्द्रित इस महा अभियान के तहत मध्यप्रदेश में करीब 7 हजार 300 करोड़ रुपये व्यय कर इन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये ठोस प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के 11 जिलों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनुपपुर, शहडोल, जबलपुर, कटनी, मैहर, सोधी एवं सिंगरौली में 2 हजार 569 ग्रामों एवं बसाहटों में करीब 4 लाख 53 हजार 320 बैगा, 10 जिलों शुरुपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, मुँरगा, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन एवं पिण्ड में 2 हजार 617 ग्रामों एवं बसाहटों में 6 लाख 86 हजार 986 सहरीया तथा 3 जिलों छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर एवं सिवनी में 315 ग्रामों एवं बसाहटों में 45 हजार 68 भारिया वर्ग के जनजातीय बंधु निवास करते हैं। पीएम जनमन के अधीन वर्तमान माली साल में अब तक हितग्राहीमूलक योजना में 11 लाख 74 हजार 780 आधार कार्ड, 5 लाख 46 हजार 620 जनधन बैंक खाते, 6 लाख 33 हजार 15 आयुष्मान कार्ड, 10 लाख 37 हजार 538 जाति प्रमाणपत्र, 65 हजार 25 किसान रेंटिड कार्ड, 86 हजार 667 पीएम किसान सम्मान निधि प्रकरण एवं 2 लाख 97 हजार 454 राशन कार्ड बनाये गये हैं। अधोसंरचना विकासमूलक योजना में अस्थायी रूप से 75 मोबाइल मेंडिकल यूनिट्स शुरू कर दी गई हैं। सितम्बर 2024 तक 66 मोबाइल मेंडिकल यूनिट्स स्थायी रूप से प्रारंभ होकर कार्य करने लगेगी। आवास योजना में 99 हजार 780 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं। करीब 79 हजार 706 हितग्राहियों को उनकी पात्रतासुर राशि देकर 12 हजार 954 आवास तैयार कर हितग्राहियों को दे दिये गये हैं। पीएम जनमन में पहले चरण में 146 बसाहटों में 294 कि.मी. लंबाई की 125 सड़कें मंजूर की गई हैं। दूसरे चरण में 51 बसाहटों में 180.29 कि.मी. लंबाई की 40 सड़कों की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। हर घर नल से जल योजना में 3 लाख 15 हजार 83 परिवारों में से 1 लाख 46 हजार 666 परिवारों को नल कनेक्शन दिये गये हैं। लक्षित अंचलों के समग्र कल्याण के लिये 125 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 7500 लाख रुपये मंजूर किये गये, जिसमें से 2598.75 लाख रुपये जारी भी कर दिये गये हैं। पीएम जनमन के अधीन ऊर्जा विभाग की हर घर बिजली प्रदाय योजना में करीब 149.88 लाख रुपये की लागत से दो चरणों में 27 हजार 356 लक्षित परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे।

मैहर कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

विभागीय अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश



मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। कलेक्टर कार्यालय मैहर के सभागार में सोमवार को संपन्न राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड ने राजस्व वसूली और सीमांकन की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एसडीएम रामनगर डॉ. आरती सिंह एवं सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि तहसील अमदरा में सीमांकन की प्रगति धीमी है। लेकिन रामनगर में पिछले 6 माह से 1 वर्ष के बीच 11 प्रकरण लंबित हैं तथा अमरपाटन में 6 प्रकरण लंबित हैं।

इसी प्रकार झिन्ना में बंटवारे के 2 प्रकरण दो वर्ष से लंबित है। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि पिछले 6 माह से लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करें। कलेक्टर ने तहसीलदार को नामांतरण के लिए मैहर में 1, नादान में 3 वसईयत के प्रकरणों को 15 दिवस के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार रामनगर तहसील के नामांतरण के 20 प्रकरण में से 11 लंबित वसईयत के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। नामांतरण के तहसील ताला में पिछले 1 साल के लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करने के आदेश दिये। कलेक्टर ने जिले के

एसडीएम को ई-केवाईसी, पीएम किसान, समग्र लिफिंग, सीएम किसान, सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग और नक्शा तरमीम करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व के प्रकरणों में कोई प्रगति नहीं पाई जा रही है। वहीं निराकरण की स्थिति उचित नहीं पाए जाने पर लगातार मॉनिटरिंग की जायेगी। भू-अर्जन के पीएचई का 1 तालाब, डब्ल्यूआरडी 1 तालाब, एनएचआई 1 तालाब एवं बेला रिंग रोड के एनवीडीए बरगी नहर के प्रकरणों को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में मैहर, अमरपाटन और रामनगर को बी ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य दिया

राजस्व की महत्वपूर्ण और मूल कड़ी है पटवारी

कलेक्टर ने नये पटवारियों को दिये टिप्स और प्रोत्साहन

मीडिया ऑडिटर, सतना निप्र। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल कड़ी होता है। सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों एवं कार्यों में पटवारी का प्रतिवेदन ही आधार होता है। सतना और मैहर जिले में नये पदस्थ 65 पटवारियों को कलेक्टर ने निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाने के टिप्स के साथ ही राजस्व परिवार में शामिल होने की शुभकामनायें दीं। कलेक्टर ने कहा कि रामपुर बधेलान तहसील में सोमवार को आयोजित नवीन पटवारियों के परिचय कार्यक्रम में अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े, अधीक्षक भू-अभिलेख एमएल तिवारी, पटवारी बुजेश निगम ने कुशल कार्य प्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्स दिये।



से सीखते हैं। उन्होंने कहा कि नव पदस्थ पटवारी सीखने की प्रेरि या से बचे नहीं, धैर्य और संयम रखें, जो सही और उचित हो वही करें। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर सीनियर पटवारी या राजस्व कार्यों के जानकार किसी अधिकारी-कर्मचारी से सलाह लेने में कतरई पुरेज नहीं करें।

राजस्व के पार्ट में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो पटवारी ग्रामीण परिवृश्य के है वह जानते है कि गांव में पटवारी की सबसे ज्यादा इज्जत होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में जनता की भलाई का अवसर सब को नहीं मिलते हैं। आप अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो अच्छे कार्यों

से लोगों की अनजाने में सच्ची सेवा कर सकते हैं। लोगों से जितना अधिक सम्पर्क बनायेंगे, छोटी-छोटी स्थानीय समस्याओं का उतना ही त्वरित निदान होगा। राज्य शासन ने हर कार्य को करने की समय सीमा तय कर रखी है। हमारी कोशिश हो कि राजस्व कार्य समय पर निराकृत हो। ग्रामीण क्षेत्र और हल्के में पहुंचने